शिमला से प्रकाशित
सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित
शैल
निष्पक्ष एवं निर्भीक
साप्ताहिक समाचार
प्रकाशन का 49 वां वर्ष
ई-पेपर
www.facebook.com/shailsamachar
प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक
वर्ष 49 अंक-22 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 20-27 मई 2024 मूल्य पांच रूपये

भ्रष्टाचार पर सुक्खू और सुधीर हुये आमने-सामने

- सुक्खू ने सुधीर को दी भू माफिया की संज्ञा
- सुधीर ने विलेज कामन लैण्ड और सीलिंग एक्ट की अवहेलना के मामले उठाये
- विलेज कामन लैण्ड पर 2011 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बढ़ सकती है मुश्किलें
- केंद्रीय ऐजैन्सियों के दखल की संभावना बनी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस लोकसभा और छः विधानसभा उपचुनावों को भाजपा द्वारा धन बल के सहारे उनकी सरकार को गिराने के आरोप के गिर्द केन्द्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में वह कांग्रेस के छः बागीयों के भाजपा में शामिल होने पर उन्हें बिकाऊ और खनन माफिया तथा भू-माफिया करार दे रहे हैं। इसी कड़ी में देवेन्द्र भुट्टो और उनके बेटे के खिलाफ देहरा में एक एफ आई आर भी दर्ज हुई है। बिकाऊ के संबोधन पर इन बागीयों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि के मामले भी दायर कर रखे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री

अपने आरोपों को हर दिन हर मंच से जिस तरह दोहराते जा रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आरोप उनकी चुनावी रणनीति का केन्द्रीय बिन्दु हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुये मुख्यमंत्री ने धर्मशाला उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र जग्गी की चुनावी जनसभा में सुधीर शर्मा को भू-माफिया करार दिया। सुधीर शर्मा के खिलाफ आरोप लगाया कि उसने अपने ड्राइवर नेक राम के नाम पर 82 संपत्तियों में दस करोड़ निवेश किया है। दुबई, पालमपुर, शिमला, मनाली और चण्डीगढ़ में भी यह संपत्तियां होने का दावा किया और कहा कि यह निवेश पिछले तीन वर्षों में हुआ तथा सरकार इसकी जांच करवा रही है। पत्रकार वार्ता में भी यह आरोप लगाया लेकिन इसके कोई दस्तावेजी प्रमाण जारी नहीं किये।

मुख्यमंत्री के इन आरोपों का जवाब देते हुये सुधीर शर्मा ने चुनौती दी है कि यदि उनके पास चुनावी शपथ पत्र से अधिक कोई संपत्ति निकल जाती हैं तो वह उसे सरकार के नाम करवा देंगे। नेकराम उनका ड्राइवर नहीं बल्कि धर्मशाला में एक संपन्न परिवार का व्यक्ति है। सुधीर शर्मा ने इन आरोपों पर मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का एक और मुकद्दमा दायर करने का ऐलान किया है। सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उनके सगे भाई के राजीव के नाम 20 हैक्टेयर. से अधिक के गैर मुमकिन दरिया की सेल डीड कैसे हुई। सुधीर शर्मा ने नादौन में ही मुख्यमंत्री के निकटस्थों द्वारा 2.50 लाख में गैर मुमकिन दरिया खरीद कर उसे 6.72 करोड़ में एचआरटीसी को कैसे बेच दिया गया? 2.50 करोड़ के जीएसटी की राहत एक उद्योगपति को कैसे दे दी गयी? सुधीर शर्मा ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही भ्रष्टाचार के खुलासे दस्तावेजों के साथ और किये जायेंगे।

सुधीर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री के सगे भाई राजीव सिंह के नाम 29-56-42 हैक्टेयर गैर मुमकिन दरिया की सेल डीड होना अपने में एक गंभीर आरोप है। क्योंकि हिमाचल में लैंड सीलिंग एक्ट लागू है जिसके मुताबिक प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के पास 300 कनाल से अधिक जमीन हो नहीं सकती। फिर नादौन रियासत की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि 229 गांव में फैली इस रियासत के राजा नादौन को 11-3-1897 को तब वित्तायुक्त पंजाब द्वारा जागीर दी गयी थी जिस पर स्थानीय लोगों के बर्तनदारी हक बदस्तूर रखे गये थे। 1971 में जब हिमाचल में लैण्ड सीलिंग एक्ट आया तब राजा नादौन की 1,59,986 कनाल जमीन का मामला राजस्व अदालतों में पहुंचा। जिसमें से 515 कनाल 14 मरले जमीन नौरा गांव में चाय बागान के नाम पर सीलिंग से बाहर रखी गयी। इसी तरह नादौन के ही कलूर गांव में 1224 कनाल 4 मरले भू-दान यज्ञ बोर्ड के नाम पर होने से इसे भी सीलिंग से बाहर कर दिया गया। 1,01,391 कनाल 17 मरले बंजर कदीम थी। यह सारी जमीने 1974 में राजस्व अदालत के फैसले के तहत विलेज कामन लैण्ड घोषित हो गयी। अब नियम है विलेज कामन लैण्ड की खरीद बेच नहीं हो सकती। इसमें से केवल भूमिहीन, हरिजन या अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन को ही कुछ जमीन गुजारे के लिये दी जा सकती है। या ऐसी जमीन पर सरकारी अस्पताल या स्कूल आदि ही हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 28-1-2011 को जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब सरकार एवं अन्य में दिये फैसले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को विलेज कामन लैण्ड की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि Before parting with this case we give directions to all the State Governments in the country that they should prepare schemes for eviction of illegal/unauthorized occupants of Gram Sabha/Gram Panchayat /Poramboke/Shamlat land and these must be restored to the Gram Sabha/Gram Panchayat for the common use of villagers of the village. For this purpose the Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the Governments. The said scheme should provide for the speedy eviction of such illegal occupant, after giving him a show cause notice and a brief hearing. Long duration of such illegal occupation or huge expenditure in making constructions thereon or political connections must not be treated as a justification for condoning this illegal act or for regularizing the illegal possession. Regularization should only be permitted in exceptional cases e.g. where lease has been granted under some Government notification to landless labourers or members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land.

23. Let a copy of this order be sent to all Chief Secretaries of all States and Union Territories in India who will ensure strict and prompt compliance of this order and submit compliance reports to this Court from time to time.

24. Although we have dismissed this appeal, it shall be listed before this Court from time to time (on dates fixed by us), so that we can monitor implementation of our directions herein. List again before us on 3.5.2011 on which date all Chief Secretaries in India will submit their reports. इन निर्देशों से स्पष्ट है विलेज कामन लैण्ड की खरीद बेच नहीं हो सकती। इसी के साथ 29-56-42 हैक्टेयर जमीन लैण्ड सीलिंग एक्ट के तहत नहीं हो सकती।

सुधीर शर्मा के यह आरोप अपने में बहुत गंभीर हैं और एक तरह से केंद्रीय ऐजैन्सियों के दखल की भूमिका तैयार करते हैं। क्योंकि विलेज कामन लैण्ड में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना है। लैण्ड सीलिंग एक्ट में यह बड़ा सवाल हो जाता है कि आज भी प्रदेश में किसी व्यक्ति के पास तय सीमा से अधिक जमीन

हो कैसे सकती है। बल्कि 2023 में सरकार ने जब सीलिंग एक्ट में संशोधन किया तब इस आश्य की कोई रिपोर्ट नहीं ली गयी कि इस समय कितने लोगों के पास सीलिंग से अधिक जमीन है। इस पर संबंधित प्रशासन क्यों अनजान रहा है।

नकल जमाबन्दी
पटवार वृत गारनी
साल 2009-2010

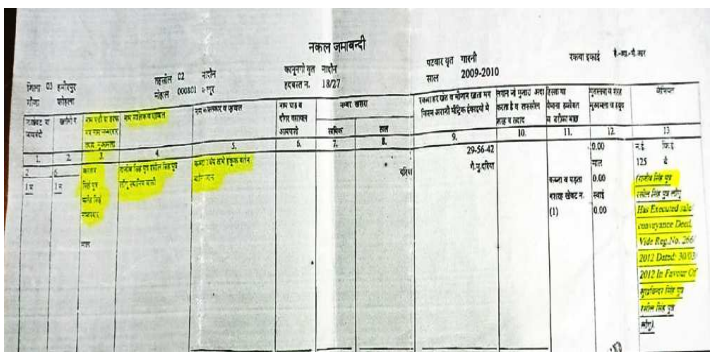

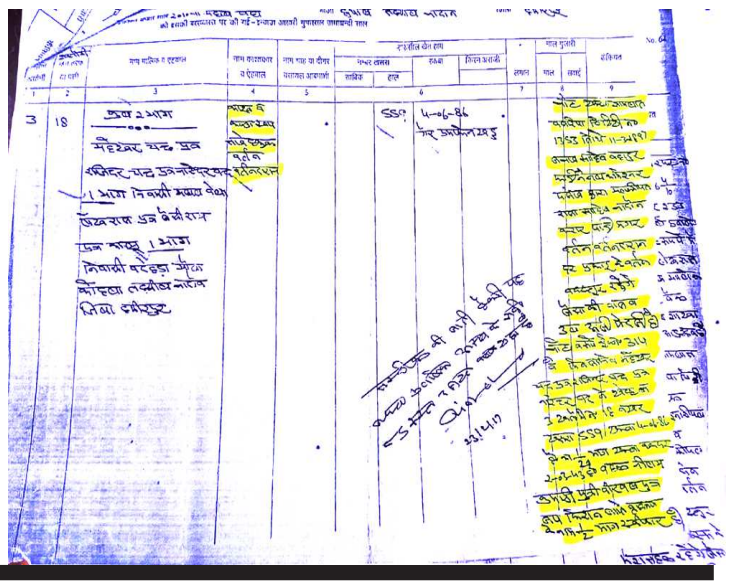

भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज और भी अधिक प्रासंगिक:राज्यपाल

शिमला/शैल। किन्नौर, लाहौल-स्पीति बौद्ध सेवा संघ शिमला द्वारा इंडो-तिब्बत फेंडशिप सोसायटी शिमला के सहयोग से आज भगवान बुद्ध की 2568वीं जयन्ती के अवसर पर दोरजे डरैक बौद्ध विहार पंथाघाटी

शिमला में समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्यातिथि रहे।

राज्यपाल ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान बुद्ध द्वारा दी गई करूणा, शांति तथा मोक्ष की शिक्षाएं समय, संस्कृति तथा सरहदों से परे करोड़ों लोगों को आत्मिक शांति तथा सार्वभौमिक भाईचारे के पथ पर चलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका संदेश आज और भी ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि हम इस आधुनिक संसार में प्राय: मतभेद और भौतिकवाद से जूझ रहे हैं। भगवान बुद्ध का जीवन तथा इनकी शिक्षाएं आत्मविश्लेषण, नैतिक जीवनशैली तथा ज्ञान की खोज की महत्वता पर बल देती हैं। उनके चार महान सत्य तथा अष्टांगिक मार्ग व्यक्तिगत तथा सामूहिक सौहार्द प्राप्त करने का उत्तम साधन है जो सदैव प्रासंगिक रहेगा। ये सिद्धान्त हमें हमारी पीड़ा का सामना करने, इसके कारण समझने तथा पीड़ा से मुक्ति पाने के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान संदर्भ में ये शिक्षाएं हम में सहनशीलता, सहानुभूति तथा परस्पर सम्मान की भावना जागृत करती हैं। ये हमें सांसारिक लगाव की अनस्थिरता तथा सचेतना व करूणा आधारित जीवन की महता को समझने में सहायता करते हैं।

राज्यपाल ने किन्नौर व लाहौल-स्पीति के बौद्ध समुदायों तथा इंडो-तिब्बत फेंडशिप सोसायटी के प्रयासों की सराहना की और कहा कि उनके प्रयास बौद्ध धर्म की समृद्ध विरासत के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

शिव प्रताप शुक्ल ने इन समुदायों द्वारा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक महता को बनाए रखने के लिए समर्पण भाव से किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इनके प्रयासों के फलस्वरूप समाज में शांति, अहिंसा तथा करूणा का महत्व बढ़ रहा है तथा नई पीढ़ी प्रेरित हो रही है।

उन्होंने कहा कि यह त्योहार भारत और तिब्बत के लोगों के मध्य गहरी मित्रता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक भी है। इस अवसर पर हमारा साझा इतिहास तथा सांस्तिक रिश्ते और मजबूत होते हैं, जिससे पारस्परिक सौहार्द बढ़ता है। उन्होंने लोगों से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को दैनिक जीवन में अपनाने के प्रयास करने तथा दुनिया में करूणा, ज्ञान और शांति को प्रोत्साहित करने का आहवान किया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर यांग्सी रिनपोचे को सम्मानित किया।

राज्यपाल ने भारतीय समुदाय से सहायक प्रोफेसर डॉ. श्रवण कुमार तथा तिब्बती समुदाय से भिक्षु शेडुप वांग्याल को भारत-तिब्बत मैत्री सम्मान-2024 प्रदान किया।

इससे पूर्व, इंडो-तिब्बत फेंडशिप सोसायटी शिमला के उपाध्यक्ष छेरिंग दोरजे ने राज्यपाल का स्वागत किया।

किन्नौर, लाहौल-स्पीति बौद्ध सेवा संघ शिमला के सदस्य ज्ञान नेगी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में अध्ययनरत लाहौल-स्पीति के विद्यार्थियों तथा तिब्बती स्कूल शिमला के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।

राज्यपाल ने दोरजे डरैक बौद्ध विहार में प्रार्थना भी की।

इस अवसर पर इंडो-तिब्बत फेंडशिप सोसायटी शिमला के अध्यक्ष तथा किन्नौर, लाहौल-स्पीति बौद्ध सेवा संघ के अध्यक्ष वी.एस. नेगी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

वनों की आग पर नियंत्रण पाने के लिए जन सहभागिता नितांत आवश्यक: मुख्य सचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने प्रदेश में वनों को आग से बचाने के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि वन हमारी अमूल्य सम्पदा है जिसकी सुरक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। वनों में लगने वाली आग पर नियंत्रण पाने के लिए जन सहभागिता और लोगों को जागरूक करना अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को वनों में आग लगने पर उसे बुझाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि जंगल में धुंआ या आग की जानकारी मिलने पर निकटतम वन विभाग कार्यालय या आपातकालीन सेवाओं के टोल-फ्री नम्बर-1077 और 1070 पर सूचना अवश्य दें।

मुख्य सचिव ने कहा कि आग लगने का कारण बनने वाली गतिविधियों जैसे वन क्षेत्रों में जलती हुई सिगरेट फेंकना, प्रतिबंधित क्षेत्रों में कैंप फायर करना या जंगलों के पास आतिशबाजी इत्यादि बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आमजन को वनों की आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों और अग्निशमन के प्रयासों में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने लोगों से अवैध रूप से जंगल में आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी हिमाचल प्रदेश वन विभाग और कानून प्रवर्तन एंजेंसी को देने का आहवान किया।

प्रदेश के लगभग 27.73 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र है। प्रदेश के 2759.62 किलोमीटर क्षेत्र में चीड़ के वन हैं। चीड़ के वृक्ष आग की घटनाओं के लिए अति संवेदनशील है। प्रदेश के वन क्षेत्र में वर्ष 2023-24 के दौरान आग लगने की घटनाओं से काफी क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

मुख्य सचिव ने कहा कि वनों को आग से बचाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी उपाय किए गए हैं। विभाग को मल्टी यूटीलिटी व्हीकल, ब्लोवेग इत्यादि उपलब्ध करवाए गए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन की सहायता से निगरानी का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वयसेवकों व गैर सरकारी संगठनों के सदस्य पंजीकृत किए गए हैं और इन्हें संबंधित क्षेत्रों में जंगल की आग के बारे में सूचित किया जाता है।

एच.आई.वी. और एड्स खत्म करने के लिए समुदाय को आगे आना होगा:राजीव कुमार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी शिमला में परियोजना निदेशक राजीव कुमार ने सामुदायिक प्रणाली सुदृढ़ीकरण के तहत राज्य कम्युनिटी रिसोर्स ग्रुप कमेटी की अध्यक्षता की जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ समुदाय से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया।

परियोजना निदेशक ने कहा कि एच.आई.वी. और एड्स को खत्म करने के लिए समुदाय को खुद आगे आना होगा जिससे प्रदेश में संक्रमित रोग को फैलने से रोका जा सके। देश में कोई भी नया संक्रमण एच.आई.वी. और एड्स का ना हो खासकर उन लोगों की वजह से जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं और जिनको इस बिमारी के प्रति अभी भी सही जानकारी नहीं है। इस संदर्भ में कम्युनिटी चौपियंस के माध्यम से उच्च जोखिम समूह के प्रति जागरुकता बढ़ाई जा रही है। राजीव कुमार ने नशा मुक्ति व यौन रोगों की रोकथाम के लिए जागरुकता बढ़ाने के लिए समुदाय के साथ-साथ विभागों की भागीदारी पर बल दिया और विभिन्न विभागों से अनुरोध किया कि वह इस बीमारी से ग्रसित लोगों के साथ गोपनीयता बनाए रखेंगे तो अन्य समुदाय भी आगे आ सकते हैं जो इस बीमारी की वजह से झिझक महसूस करते हैं। इस अवसर पर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज्य आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, पुलिस विभाग और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

शहरी क्षेत्रों में मतदान उदासीनता दूर करने के लिए साइकिल सवारों ने किया मतदाताओं को जागरूक

शिमला/शैल। राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं विशेषकर शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए साइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के सहयोग से हमीरपुर तथा किन्नौर को छोड़कर सभी

जिलों में साइकिल रैलियां आयोजित की गई। प्रदेश के दस जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने संबंधित जिलों में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने ऐतिहासिक रिज से साइकिल सवारों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर मुख्यातिथि मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने भी पुलिस अधीक्षक शिमला सहित अन्य अधिकारियों के साथ शिमला में साइकिल चलाकर रैली में भाग लिया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन विभाग के साथ मिलकर पूरे कार्यक्रम का संचालन करने के लिए साइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष मोहित सूद को बधाई दी। उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई भी दी।

उन्होंने कहा कि ये रैलियां मतदाताओं, विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं और युवाओं को मतदान का महत्त्व बताने के लिए आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि राज्य भर में इन साइक्लिंग रैलियों में लगभग 2000 प्रतिभागियों ने भाग लिया है जो काफी सराहनीय है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रथम जून, 2024 को लोकसभा चुनाव के इस महापर्व में सभी की भागीदारी प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमेशा मतदान प्रतिशत में वृद्धि देखी गई है और राज्य के लोग, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में काफी उमंग और उत्साह रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में 76 प्रतिशत मतदान हुआ था और इस बार इस आंकड़े से भी आगे जाने का लक्ष्य है।

मनीष गर्ग ने नारा लेखन सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं और सबसे कम उम्र और सबसे उम्रदराज साइकिल सवार को पुरस्कार भी प्रदान किए। उन्होंने 'द डेमोक्रेसी वैन'को भी हरी झंडी दिखाई, जो लोगों में स्वेच्छा से मतदान के लिए जागरूक करेगी।

साइकिल सवारों ने दस जिलों में 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर शहरी मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित किया ताकि चुनाव के दौरान शहरी मतदाताओं की उदासीनता को समाप्त किया जा सके।

साइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष मोहित सूद ने कहा कि साइकिल सवारों ने लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय की। साइकिल सवार रिज मैदान से विधानसभा, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, आईजीएमसी, संजौली, नवबहार तथा राज भवन होते हुए रिज मैदान पर वापस आये। कार्यक्रम के दौरान एपीजी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने मतदान के महत्त्व पर आधारित एक नाटक प्रस्तुत किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

द्वितीय व्यय जांच में नौ प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टरों की हुई जांच

शिमला/शैल। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टर की दूसरी जांच डीआरडीए हॉल में शनिवार को व्यय पर्यवेक्षक आईआरएस अधिकारी राकेश झा द्वारा की गई। जांच में कुल 10 प्रत्याशियों में से 9 प्रत्याशियों के अधिकृत एजेंट अपने व्यय विवरण की जांच हेतु उपस्थित हुए। एक निर्दलीय प्रत्याशी राखी गुप्ता का कोई एजेंट व्यय जांच के लिए उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार के खर्चे की कड़ी निगरानी की जा रही है। व्यय निगरानी का मकसद सभी प्रत्याशियों को लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करवाना है। प्रत्याशियों के व्यय रजिस्टर की तीसरी जांच अब 29 मई को होगी। पहली जांच 21 मई को की गई थी।

व्यय पर्यवेक्षक ने इस दौरान प्रत्याशियों के अधिकृत एजेंटों से चुनाव प्रचार के खर्च का पूरा ब्यौरा रोजाना रजिस्टर में दर्ज करने को कहा है ताकि सहायक व्यय पर्यवेक्षकों एवं अकाउंटिंग टीमों द्वारा बनाए गए शैडो रजिस्टर से इसका मिलान कर खर्च का सही आकलन किया जा सके। झा ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करते ही उम्मीदवार के खर्चे की गणना शुरू हो जाती है और चुनाव परिणाम घोषित होने तक जारी रहती है।

उन्होंने बताया कि चुनावी खर्चे का नियमानुसार हिसाब न देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है और उनके चुनाव लड़ने पर 3 साल तक का प्रतिबंध लग सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित खर्च 95 लाख की सीमा से ज्यादा खर्चा पाए जाने पर चुनाव में विजयी हो जाने के बाद भी सदस्यता रद्द हो सकती है।

निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए व्यय पर्यवेक्षक ने सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे आदर्श आचार संहिता की अक्षर: अनुपालना सुनिश्चित करने में अपना सहयोग दें।

व्यय जांच में एडीसी मंडी रोहित राठौर, सहायक व्यय पर्यवेक्षक और चुनाव प्रत्याशियों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

मोदी ने पूरी ताक़त के साथ राज्य सरकार को गिराने का प्रयास किया: प्रियंका

शिमला/शैल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने काँगड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार आनन्द शर्मा के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने चंबा और शाहपुर के चंबी में जनसभाएँ की और कांग्रेस के सभी

उम्मीदवारों का जिताने की अपील की। प्रियंका गांधी ने कहा कि हिमाचल देवभूमि और वीरभूमि है, यहां के लोग ईमानदार हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साज़िश के तहत पूरे धनबल के साथ राज्य के ईमानदार लोगों की चुनी हुई ईमानदार सरकार को गिराने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मोदी को हिमाचल प्रदेश के लोगों से कोई प्यार नहीं है, बल्कि भाजपा नेताओं का एकमात्र मक़सद सभी हथकंडे अपनाकर सत्ता हासिल करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना घर बताते हैं, लेकिन जब राज्य में आपदा आयी तो वह एक बार भी हिमाचल प्रदेश नहीं आये और केंद्र की ओर से आपदा प्रभावितों के लिए एक पैसा तक नहीं दिया।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पिछले दस साल में मोदी सरकार ने केवल अपने खरबपति मित्रों को खुश करने की नीतियाँ बनाई। कर्मचारियों को पुरानी पैन्शन देने के लिए केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं हैं, जबकि उन्होंने उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज़ माफ़ किये और देश के संसाधन उनको सौंपे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सेब के कोल्ड स्टोर उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए हैं, जो सेब के दाम कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके कारण सेब बागवानों को सेब के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, जिससे सेब बाग़बानों को नुकसान हुआ। कांग्रेस 55 साल तक सत्ता में रही, लेकिन कभी भी जनता के हितों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ग़लत नीतियों के कारण महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ी है। इन्हीं ग़लत नीतियों का नतीजा अग्निवीर योजना है, जिसमें चार साल बाद युवा बेरोज़गार हो जाता है, उन्हें पेंशन नहीं मिलती और शहादत पर उन्हें कोई आर्थिक मदद भी नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही वन रैंक – वन पेंशन योजना दी थी।

प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने के बाद महिलाओं को 8500 रुपए प्रति माह और एक साल में एक लाख रुपए दिए जाएँगे। सरकारी क्षेत्र में ख़ाली पड़े 30 लाख पदों को भरा जाएगा और इसमें महिलाओं को 50 फ़ीसदी आरक्षण देंगे। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय दोगुना किया जाएगा और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की क़ानूनी गारंटी का अधिकार देंगे। इसके अतिरिक्त किसान की फसल को नुक़सान होने पर 30 दिन में मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा, किसानों की क़र्ज़ माफ़ी के लिए आयोग बनाया जाएगा और कृषि उपकरणों पर सीएसटी ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार राजस्थान की तर्ज पर देश भर में 25 लाख रुपए का फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा का लागू किया जाएगा और ग्रेजुएट युवाओं के लिए एपरेंटिसशिप कार्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें प्रति माह 8500 रुपए का भत्ता प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा डबल इंजन सरकार की बात करती थी, लेकिन कांग्रेस डबल सेवा की बात करती है, इसलिए केंद्र में कांग्रेस को सरकार बनाइए। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष में भाजपा सबसे अमीर पार्टी बन गई क्योंकि छापे मारकर चंदा वसूल किया गया।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार तमाम मुश्किलों के बावजूद ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करने के लिए दिन – रात काम कर रही है और सभी गारंटियों को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर नीयत साफ तो कोई भी सरकार अच्छा कर सकती है और कांग्रेस की सरकार ने यह करके दिखाया है। पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए बहाल की है और 1500 रुपए पेंशन की योजना को भी लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से कटौती कर प्रभावित परिवारों की मदद की। उन्होंने कहा कि सेवा ही कांग्रेस पार्टी की परंपरा है। उन्होंने कहा कि काँगड़ा लोकसभा क्षेत्र के लोग कांग्रेस प्रत्याशी आनन्द शर्मा पर भरोसा कर सकते हैं और उन्हें इस क्षेत्र से विजयी बनाएँ। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सभी वादों को पूरा किया जाएगा।

पीएम मोदी ने 22 लोगों के 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया: राहुल

शिमला/शैल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सिरमौर जिला के नाहन में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के चारों लोकसभा उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए कहा कि मैं और प्रियंका दिल्ली में आपके सिपाही हैं और हिमाचल प्रदेश की आवाज़ को दिल्ली में बुलंद करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में आपदा आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की कोई मदद नहीं की। प्रदेश में आपदा से 22 हजार परिवार प्रभावित हुए और केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया। नुकसान से 9000 करोड़ रुपए भी अभी तक केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को नहीं दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अडानी और मीडिया की पार्टनर्शिप के कारण हिमाचल के सेब बाग़बानों को सही दाम नहीं मिल रहा है। मोदी ने सेब स्टोरेज का सारी फैसिल्टी एक आदमी को दे दी है और वह सेब के दाम को कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्रे नरेंद्र देश के 20 – 25 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। देश के सात एयरपोर्ट अडानी की कंपनी को दे दिए गए हैं और हथियार बनाने का काम भी अडानी की कंपनी कर रही है। पूरा देश जानता है कि जब तक मोदी सत्ता में है तब तक अडानी की कंपनी मुनाफ़ा कमाएगी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के मात्र 22 लोगों को करोड़पति बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले दस वर्षों में उनका 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ किया गया है, लेकिन किसान का कर्ज माफ़ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आज मीडिया सेब के दाम, किसानों और मज़दूर की समस्याओं की चर्चा नहीं करता, बल्कि अडानी की शादी दिखाता है। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ 22 लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं और बाक़ी का देश देखता रह जाता है। भाजपा सरकार ने नोटबंदी कर करोड़ों छोटे कारोबारियों को बर्बाद कर दिया और ग़लत जीएसटी लागू किया।

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के करोड़ों लोगों को लखपति बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर हर गरीब महिला के खाते में एक साल में एक लाख रुपए डाले जाएंगे। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की क़ानूनी गारंटी दी जाएगी। सरकारी क्षेत्र में 30 लाख नौकरियाँ देंगे और मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपए करेंगे। इसके साथ ही ग्रेजुएट युवाओं को पहली नौकरी पक्की का अधिकार देंगे, जिसके तहत सरकारी कंपनियों, संस्थानों में उन्हें रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ करने के साथ – साथ आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं और आशा कार्यकर्ताओं की आय दोगुनी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह फ्री गिफ्ट नहीं है, बल्कि लोगों का अधिकार है, जिसे केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि संविधान भारत की आवाज़ है और भाजपा उस संविधान पर हमला कर रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता मज़बूती के साथ भाजपा के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि इसकी सोच हज़ारों साल पुरानी है और यह किताब देश की आवाज़ है।

इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, शिमला से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक अजय सोलंकी सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

वोट के अधिकार को ख़रीदना चाहती है भाजपा:सीएम

शिमला/शैल। सिरमौर जिला के नाहन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा जनता के वोट को अधिकार को ख़रीदना चाहती है। उन्होंने कहा

कि आज़ादी के लंबे संघर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी ने देशवासियों को वोट का अधिकार दिया, लेकिन अब भाजपा वोटों का सौदा करना चाहती है। इसलिए जन भावनाओं का सौदा करने वाली पार्टी को एक जून को सबक़ सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई अब प्रदेश की जनता लड़ेगी क्योंकि यह चुनाव भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। केवल जनता ही धनबल को हरा सकती है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव ईमानदारी और बेईमानी, सत्य और असत्य तथा धर्म और अधर्म के बीच है। लेकिन अंत में जीत ईमानदारी और सत्य की होगी, यह तय है। उन्होंने कहा कि भाजपा जब वोट से सत्ता हासिल नहीं कर पायी, तो उसने नोटों के दम पर कुर्सी हथियाने का प्रयास किया और छ: विधायकों को राजनीतिक मंडी में ख़रीदा।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को मेरे नेता कहकर संबोधित करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उनके आदेश का पूरा पालन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने देश की एकता व अखंडता के लिए 4500 किमी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो देश के एक प्रधानमंत्री के पुत्र और एक प्रधानमंत्री के पोते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक आम परिवार से राजनीति में आये एक व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया और सरकार की योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के निर्देश दिए। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं का रोज़गार मिलना चाहिए और महिलाओं को सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन दी। महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देकर हर साल उनके खाते में 18000 रुपए की राशि डाली जा रही है। विधवाओं के 27 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है और अनाथ बच्चों की देखरेख, शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार उठा रही है। क्या यह गुनाह है ?

मुख्यमंत्री ने शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी को भारी बहुमतों से जिताने की अपील की और कहा कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें और विधानसभा उपचुनाव की सभी छ: सीटें कांग्रेस पार्टी अवश्य जीतेगी।

मुख्य सचिव ने डोडरा क्वार में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जिला शिमला के रोहडू उपमंडल के सबसे दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान चुनाव तैयारियों और स्वीप गतिविधियों की समीक्षा की और लोगों को 1 जून, 2024 को मतदान करने के लिए प्रेरित किया।

लोकसभा चुनाव के दौरान डोडरा क्वार का दौरा करने और चुनाव तैयारियों का निरीक्षण करने वाले सक्सेना पहले मुख्य सचिव हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे 'वोट करेगा डोडरा क्वार' के आदर्श वाक्य के साथ 100 प्रतिशत मतदान करके एक इतिहास बनाते हुए बढ़चढ़ कर मतदान करें।

उन्होंने महिला और युवक मंडलों के अलावा स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया और स्वेच्छा से मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने उपमंडलाधिकारी कार्यालय डोडरा क्वार में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर पर हल करने का आश्वासन दिया।

उन्होंने क्षेत्र में मतदान केंद्रों और मतदान दलों को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में आवश्यक निरीक्षण किया। उपमंडलाधिकारी डोडरा क्वार धर्मेश रमोत्रा भी मुख्य सचिव के साथ थे।

इससे पूर्व डोडरा क्वार पहुंचने पर मुख्य सचिव का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी।
..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

किस पर विश्वास किया जाये एनडीए या इंडिया पर

चुनाव प्रचार अंतिम चरण पर चल रहा है। अब तक हुये मतदान के आधार पर दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया दोनों अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। मतदान प्रतिशत के आंकड़े 2019 की तुलना में बहुत नीचे हैं। कम मतदान होना इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता है कि यह मतदान सत्ता पक्ष या विपक्ष के पक्ष में जायेगा। आज भाजपा नीत गठबंधन पिछले दस वर्षो से केंद्र की सत्ता पर काबिज है। 2014 के चुनाव से पहले जिन मुद्दों पर देश में अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव के आन्दोलन आये थे उनके परिणाम स्वरुप देश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। 2014 के चुनाव में भाजपा नीत एनडीए गठबंधन केंद्र की सत्ता पर काबिज हुआ था। उस समय जो वायदे देश की जनता के साथ किये गये थे उनमें से कितने पूरे हुये हैं। यह हरेक के सोचने और समझने का विषय है। इसके बाद 2019 के चुनाव हुये और एनडीए फिर सत्ता पर पहले से ज्यादा बहुमत के साथ काबिज हुई। आज 2024 के चुनाव में मोदी भाजपा ने 400 पार का नारा दिया है। लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में जो वायदे किये गये थे उनमें से कितने पूरे हुये हैं। क्या इस पर कोई विधिवत चर्चा आयोजित हो पायी है शायद नहीं। यह सोचने का विषय है 2014 में तब की सरकार को भ्रष्टाचार का प्रयाय करार दिया गया था। अन्ना आन्दोलन का केंद्रीय मुद्दा लोकपाल की स्थापना था। 2014 के सत्ता परिवर्तन के बाद लोकपाल की स्थापना हुई है। लेकिन लोकपाल के पास भ्रष्टाचार के कितने और कौन से मामले गये और उनके परिणाम क्या रहे हैं क्या इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से बाहर आयी है। शायद नहीं। इस चुनाव में भी यूपीए सरकार के समय के घोटाले की सूची भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल की चुनावी जनसभा में रखी है। लेकिन उसमें यह नहीं बताया कि इन पर कारवाई करने की जिम्मेदारी किसकी थी। 2014 से 2024 तक कांग्रेस और अन्य दलों से भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे नेता भाजपा में शामिल हुये हैं उनके ऊपर लगे आरोपों का क्या हुआ। जब 2014 और 2019 में किये गये वायदे पूरे नहीं हुये तो 2024 में किये जा रहे वायदों पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। क्या आज आरएसएस के ही अनुसार अनुषांगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच बंद नहीं हो चुके हैं? क्या यह नीतियों या नीयत में बदलाव के परिणाम नहीं हैं। इस चुनाव में आरएसएस ने भाजपा का चुनाव में समर्थन नहीं करने का आहवान किया है। लेकिन इस आहवान का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया है। आज देश में भाजपा मोदी के विकल्प के रूप में कांग्रेस और राहुल गांधी को देखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारें क्यों सत्ता से बाहर हो गयी इसका कोई जवाब जनता में नहीं आया है। स्वभाविक है कि बदलाव बनने के लिये सरकार में परफारमैन्स करके दिखाना होगा। इस समय हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पन्द्रह माह से सत्ता में है। क्या यह सरकार पन्द्रह माह में परफारमैन्स कर पायी है शायद नहीं। यह सरकार भी स्पष्टवादी मीडिया की विरोधी है। बेवाक लिखने वालों का गला घोटने के लिये किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में जब विकल्प की स्थिति ऐसी होगी तो उस पर कैसे विश्वास किया जा सकेगा? यह सवाल अपने में बड़ा होता जा रहा है। इसके परिणाम क्या होंगे यह और भी गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में यह आंशका बढ़ती जा रही है कि इस बार चुनाव परिणाम के साथ ही कहीं अराजकता अपने पांव न पसार ले।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का 25 दिन का काउंटडाउन शुरू, 7,000 से ज्यादा योग उत्साही लोगों ने योग किया

शिमला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए 25 दिन शेष बचे हैं और इसके साथ ही बिहार के बोधगया में एक मेगा योग प्रदर्शन के साथ काउंटडाउन कार्यक्रम का समापन हुआ। इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार में किया गया। 27 मई, 2024 को सुर्योदय के साथ शुरू हुए इस आयोजन में 7000 से ज्यादा योग साधकों ने क मन योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) का पालन करते हुए योग किया। इस कार्यक्रम में लोगों के उत्साह एवं बहुमूल्य योगदान ने सामान्य जीवन में योग के महत्व को और ज्यादा मजबूत किया। सामूहिक योगाभ्यास का यह कार्यक्रम न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

आयुष मंत्रालय के कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 25 दिन शेष रहने के साथ, योग उत्सव का आयोजन बिहार के बोधगया में किया गया। इसमें विभिन्न आसन और मुद्रा जैसे प्रार्थना, योगिक सुक्सामाता, ताड़ासन, वक्रासन, पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन, त्रिकोणासन, भद्रासन आदि शामिल हैं। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक के मार्गदर्शन में उपस्थित लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इन आसनों को किया।

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई), आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक स्वायत्त निकाय है जिसने हजारों कुशल योग गुरुओं को प्रशिक्षित कर हमारे देश में योग के परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके समर्पण ने यह सुनिश्चित किया है कि पूरे देश में योग को प्रभावी तरीके से बढ़ावा दिया जाए। उनके प्रयास न केवल शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं बल्कि लोगों के बीच मानसिक और आध्यात्मिक सद्भाव में भी योगदान करते हैं। इन योग गुरुओं के प्रशिक्षण में संस्थान का योगदान भारत और उससे आगे योग के अभ्यास और दर्शन को आगे बढ़ाने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डॉ. काशीनाथ समगंडी, निदेशक, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) ने स्वागत भाषण के साथ ही कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया और प्रतिभागियों को कार्यक्रम की सफलता में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद दिया। योग के सार्वभौमिक अभ्यास को बढ़ावा देने

के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत से ही योग ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। पिछले वर्ष, दुनिया भर में 23.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 पर योग किया। आयुष मंत्रालय को विश्वास है कि इस वर्ष यह भागीदारी लगभग दोगुनी होगी।

डॉ. काशीनाथ समगंडी, निदेशक, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, भिक्खु बड़ बोधि और डॉ. राजीव लोचन दास, प्रिंसिपल एस.आर.टी.आयुर्वेद ने इस अवसर पर दीप प्रज्ज्वलित किया। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल का लाइव प्रदर्शन किया गया। एमडीएनआईवाई कार्यक्रम अधिकारी आईएन आचार्य ने सभी लोगों का स्वागत किया।

आयुष मंत्रलय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से, 100 दिन, 100 शहर और 100 संगठन वाले अभियान के भाग के रूप में सामूहिक योग प्रदर्शनों और सत्रें की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है आईडीवाई-2024 मनाने के लिए एक कार्यक्रम। इस पहल को स्कूलों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कॉलेजों, कॉरपोरेट निकायों के साथ-साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के सहयोग से किया जा रहा है।

अर्धसैनिक बलों के जवानों ने अपने-अपने क्षेत्रों में योग को बढ़ावा देने में और योग का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस प्रकार अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा, आईटी परिसंपत्तियों का उपयोग योग अभ्यास के प्रभावी प्रसार में मदद करता है, जिससे इसकी पहुंच व्यापक होती है।

लोगों तक योग की व्यापक पहुंच और जुड़ाव सुनिश्चित करते हुए, गतिशील कार्यक्रमों का आयोजन आयुष मंत्रालय, एमडीएनआईवाई और अन्य प्रतिष्ठित योग संस्थानों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्मो पर किया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर, इस आयोजन ने भौतिक स्थलों से आगे बढ़कर अपनी पहुंच का विस्तार किया, पूरी दुनिया के लोगों को योग की परिवर्तनकारी शक्ति में हिस्सा लेने के लिए सशक्त बनाया।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में दूरदर्शन की एंट्री

दूरदर्शन किसान 26 मई 2024 को दो एंकर AI कृष और AI भूमि लान्च करेगा ये एंकर देश-विदेश की पचास भाषाओं में बात कर सकते हैं

शिमला। दूरदर्शन एक और उपलब्धि हासिल करने जा रहा है क्योंकि 9 साल की अपार सफलता के बाद डीडी किसान 26 मई 2024 को एक नए रंग रूप और एक नए अंदाज के साथ, भारत के किसानों के बीच आ रहा है। जहां चैनल की प्रस्तुति एक नए अंदाज में होने जा रही है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में ये देश का पहला सरकारी टीवी चैनल बनने जा रहा है जहां । एंकर पर सभी की निगाहें रहेंगी। दूरदर्शन किसान दो AI एंकर AI कृष और AI भूमि लान्च करने जा रहा है। ये न्यूज एंकर एक कंप्यूटर हैं, जो हूबहू इंसान की तरह ही हैं और इंसानों की तरह ही काम कर सकते/सकती हैं। ये एंकर बिना रुके या फिर बिना थके 24 घंटे और 365 दिन न्यूज़ पढ़ सकते हैं।

किसान दर्शक इन्हें कश्मीर से तमिलनाडु और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देश के सभी राज्यों में देख पाएंगे। ये एंकर देश विदेश में हो रहे कृषि अनुसंधान, अनाज मंडियों में हो रही उठापटक या फिर मौसम की फेरबदल, हर आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुंचाएंगे। इन एंकर की एक खास बात यह भी है कि ये देश-विदेश की पचास भाषाओं में बात कर सकते हैं।

डीडी किसान के उद्देश्यों में शामिल कुछ खास तथ्य-

डीडी किसान देश का एक मात्र टीवी चैनल है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा किसानों को समर्पित की गई है। इस चैनल की स्थापना 26 मई 2015 को की गई थी।

डीडी किसान चैनल की स्थापना का उद्देश्य था कि वह हमेशा सजग रहते हुए मौसम, वैश्विक बाजारों इत्यादि में होने वाले बदलावों से किसानों को अवगत कराता रहे, ताकि किसान पहले से ही उपयुक्त योजनाएं बना सकें और समय पर सही निर्णय ले सकें। डीडी किसान चैनल 9 साल से इन मापदंडों पर खरा उतर रहा है।

डीडी किसान चैनल प्रगतिशील किसानों के प्रयासों को सभी लोगों के सामने लाने का काम भी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश में कृषि और ग्रामीण समुदाय की सेवा करना तथा उन्हें शिक्षित कर समग्र विकास का वातावरण बनाने की दिशा में काम करना है।

डीडी किसान चैनल कृषि की त्रिआयामी अवधारणा जिसमें संतुलित खेती, पशुपालन और वृक्षारोपण शामिल हैं, को मजबूत कर रहा है।

साइबर असुरक्षा से निपटना:एक परस्पर जुड़ी दुनिया में लचीलेपन का निर्माण

शिमला। नई दिल्ली में सीएससी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीटयूशन द्वारा संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसके तहत साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा की गई।

साइबर सुरक्षा एक गंभीर और संवेदनशील मामला है। दुनिया भर में हर साल डेटा में सेंध बढ़ने के साथ साइबर खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। आईटी सेवा प्रदाताओं की ओर से साइबर सुरक्षा उल्लंघन के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। कंपनियों को अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। डेटा सुरक्षा में किसी भी तरह का सेंध व्यापार में भारी नुकसान के साथ विश्वास और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री एस कृष्णन ने कहा, सीएससी तकनीक की पहुंच बढ़ाने और अंतिम छोर तक सूचना साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुरक्षा सिर्फ़ सिस्टम की बात नहीं है, बल्कि व्यवहार, ज्ञान और आदतों की बात भी है। हमारे प्रमुख जोखिमों में से एक अंतिम उपयोगकर्ता है जो साइबर सुरक्षा के महत्व को अनदेखा कर अक्सर पिन नंबर साझा करता है और असुरक्षा को बढ़ाता है।

श्री एस कृष्णन ने कहा, सीएससी और यूएसआई के बीच साझेदारी दो अलग-अलग दुनियाओं को जोड़ती है, जिससे हमारा डिजिटल परिदृश्य बेहतर होता है। डिजिटलीकरण न केवल उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि डेटा को केंद्रीकृत भी करता है, जिससे एक मजबूत डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। धोखाधड़ी का शिकार होने से बचने के लिए सभी को साइबर जोखिमों के बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। व्यवहार और मनोवृत्ति संबंधी आदतों मे सुधार करके, हम प्रभावी रूप से जागरूकता फैला सकते हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से, हमारा लक्ष्य नए उपायों को सीखना है जिन्हें लागू करके एमईआईटीवाई साइबर सुरक्षा रणनीतियों को मजबूत कर सकता है।

कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत करते हुए, सीएससी एसपीवी के एमडी और सीईओ श्री संजय राकेश, ने कहा, सीएससी साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव 2024 में, हम सीएससी जैसी उपयोगकर्ता एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा की व्यापक श्रेणियों पर जोर देते हैं। हमें अधिक साइबर लचीला बनने और लागत प्रभावी विकल्पों की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। यह सम्मेलन हमें मजबूत डेटा प्रबंधन और साइबर खतरों और चोरी को रोकने की रणनीतियों पर केंद्रित, साइबर सुरक्षा में सुधार के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। एक साइबर थिंक टैंक विकसित करके, हमारा उद्देश्य अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल साइबर प्रणाली बनाना है। हम साइबर सुरक्षा की दिशा में अपने प्रयासों का नेतृत्व करने और एक सुसंगत साइबर सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में काम करने के लिए एक छोटा, समर्पित समूह स्थापित करेंगे।

उभरते साइबर खतरे, रुझान और समाधान विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। चर्चा में मुख्य वक्ता थे: मेजर जनरल (डॉ पवन आनंद, (सेवानिवृत्त)(मेजर विनीत कुमार, संस्थापक साइबर पीस फाउंडेशन(कर्नल राहुल मोदगिल, सीआईएसओ, ईपीएफओ(मीटीई(के वरिष्ठ निदेशक सेवानिवृत्त, श्री राकेश माहेश्वरी, प्रमुख-समाधान वास्तुकार-सार्वजनिक क्षेत्र भारत और सार्क, श्री हीरल शर्मा, सीआईएसओ, रक्षा और विमानन, फोर्टिनेट और श्री अनुराग चंद्रा।

इस अवसर पर साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीएससी और यूएसआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

कार्यक्रम के दौरान अन्य प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे: बिजनेस हेड - साइबर सुरक्षा, मिटकैट एडवाइजरी, इंदर चौधरी, सर्ट-आईएन वैज्ञानिक एफ, आशुतोष बहुगुणा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा विद्वान, सीओई, पश्चिम बंगाल सरकार, कौशिक हलदर, फोटनेट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, रोहित भूरानी, सरकारी और पीएसयू बिजनेस- चेकपॉइंट, निदेशक, विकास अवस्थी, सीनियर प्रिंसिपल कंसल्टेंट- ट्रेंडमाइक्रो, अंकित गुगलानी।

साइबर सुरक्षा हमेशा से ही सीएससी के एजेंडे में एक प्राथमिक विषय रहा है। इसने दुनिया भर की अग्रणी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ मिलकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में साइबर रक्षक कार्यक्रम शुरू किया है। इस साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण पहल ने महिलाओं को नई प्रौद्योगिकी कौशल से लैस कर उन्हें साइबर सुरक्षा राजदूत के रूप में उभरने में मदद की है।

सीएससी एसपीवी के बारे में:

कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) डिजिटल इंडिया मिशन का एक अभिन्न अंग हैं। वे देश भर के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल इंडिया सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक्सेस पॉइंट हैं और डिजिटल इंडिया के विज़न और डिजिटल और वित्तीय रूप से समावेशी समाज के लिए सरकार के जनादेश को पूरा करने में योगदान करते हैं। सीएससी बेहतर शासन पर केंद्रित, भारत में ई-सेवाओं तक पहुँच के लिए सहायता प्रदान करते हैं। आवश्यक सरकारी और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ प्रदान करने के अलावा, सीएससी कई सामाजिक कल्याण योजनाएँ, वित्तीय सेवाएँ, शैक्षिक पाठयक्रम, कौशल विकास पाठयक्रम, स्वास्थ्य सेवा, कृषि सेवाएँ और डिजिटल साक्षरता भी प्रदान करते हैं।

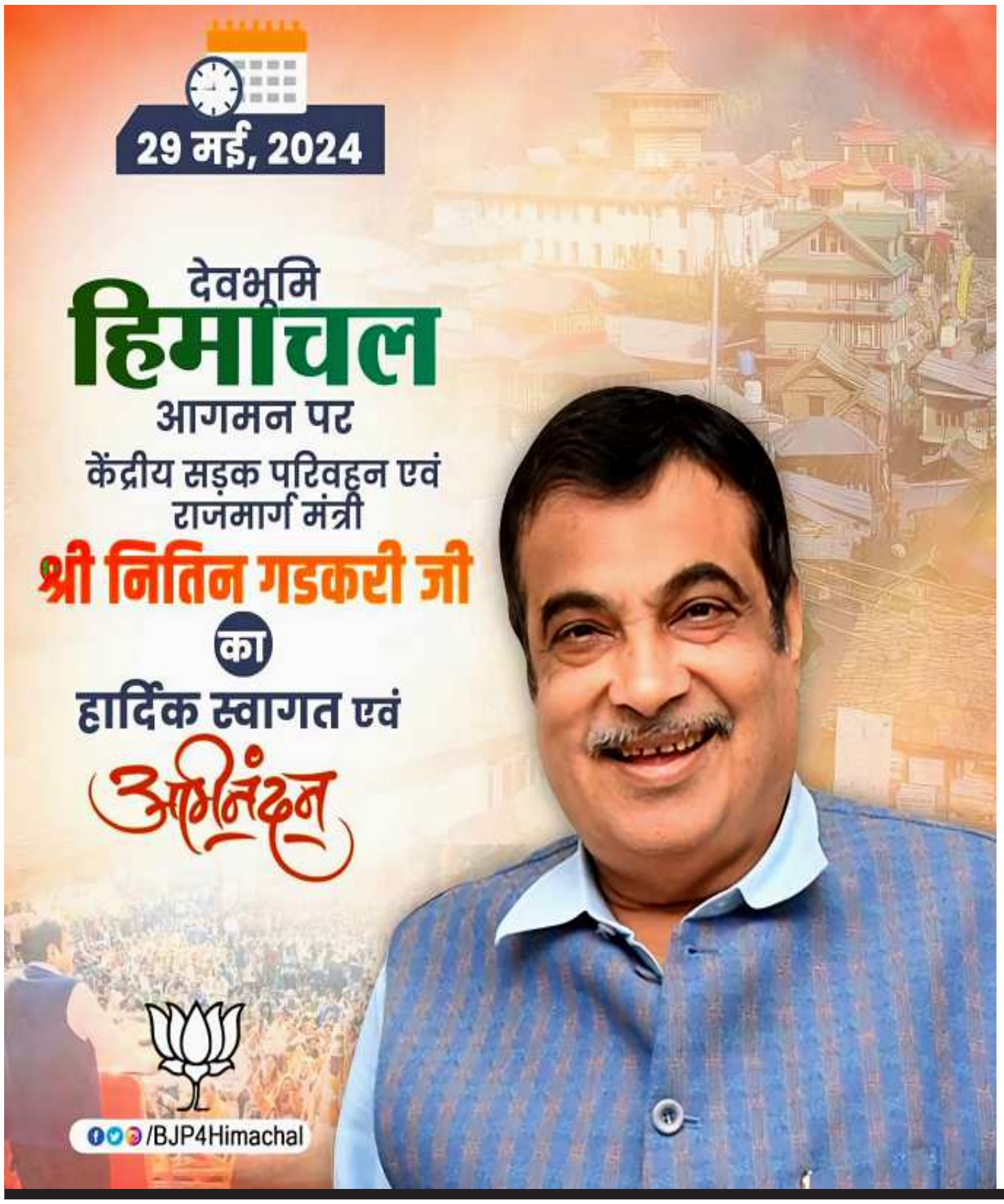

सातवें चरण में 08 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में

शिमला। लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण में 08 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 01 जून, 2024 को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव 2024 के सातवें चरण में होने वाले मतदान के लिए 08 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 57 संसदीय क्षेत्रों के लिए कुल 2105 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। सभी 08 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए चरण 7 के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 मई, 2024 थी। दाखिल किए गए सभी नामांकनों की जांच के बाद 954 नामांकन वैध पाए गए।

चरण 7 में, पंजाब में 13 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से अधिकतम 598 नामांकन फॉर्म थे, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 13 संसदीय क्षेत्रों से 495 नामांकन थे। बिहार के 36-जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से सर्वाधिक 73 नामांकन पत्र प्राप्त हुए, इसके बाद पंजाब के 7-लुधियाना संसदीय क्षेत्र से 70 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। 7वें चरण के लिए एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 16 है।

मोदी भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु, संविधान खत्म करने का ना देखें सपना:राहुल

शिमला/शैल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद राहुल गांधी ने ऊना में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु हैं। देश के सारे भ्रष्टाचारी नेता उनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जैसे ही वे लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर भगाया जा रहा है।

इलेक्टोल बांड योजना में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, केंद्र सरकार चंदा देने वालों के नाम क्यों नहीं बता रही। इस योजना के जरिये बड़ी-बड़ी-बड़ी कंपनियों को ईडी व सीबीआई का डर दिखाकर चंदा लिया गया है।

राहुल ने कहा कि भाजपा संविधान को खत्म करने का सपना न देखे। देश की जनता व कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ता इसे होने नहीं देंगे। इस चुनाव में लड़ाई संविधान को बचाने की भी है। यह संविधान की ताकत ही है कि हिमाचल अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में है। मोदी सरकार में हर चीज खतरे में है। जो मौके अमीर को और अमीर बनने के दिए जा रहे हैं, वह देश के युवाओं, गरीबों और किसानों को भी मिलने चाहिए। मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर छीन लिए हैं, 2 करोड़ रोजगार सालाना तो नहीं दिए लेकिन पूर्व यूपीए सरकार के समय जो नौकरियां मिल रही थीं, वह भी खत्म कर दीं। कांग्रेस युवाओं को रोजगार का अधिकार देगी।

उन्होंने कहा कि हमें दो तरह की सेना नहीं चाहिए। हिमाचल के युवा भी बड़ी संख्या में सेना में जाते थे, लेकिन अग्निवीर योजना आने के बाद उनका क्रेज कम हुआ है। अब सेना की दो श्रेणी हो गई हैं, एक जवान को देश के लिए बलिदान देने पर शहीद का दर्जा है, जबकि अग्निवीर को नहीं। अग्निवीर के परिवार को दूसरे जवानों की तर्ज पर सुविधाएं भी नहीं हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के युवा को पहले की तरह सेना में जाने के अवसर मिलेंगे। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने 700 किसानों को भी दिल्ली बॉर्डर पर शहीद कर दिया, लेकिन आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया। हिमाचल व अन्य प्रदेशों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, जबकि अडानी का कर्ज माफ कर दिया गया। भाजपा नेता किसानों को आतंकवादी कहते हैं। किसानों का कर्ज कांग्रेस सरकार बनाते ही माफ करेगी। किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून बनाकर देगी।

राहुल ने कहा कि भाजपा ने गोवा, अरुणाचल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकारें चोरी की, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पैसे के दम पर कांग्रेस सरकार को नहीं गिरा पाए। प्रदेश की जनता समझदार है और भाजपा के राजनीतिक भ्रष्टाचार को समझ चुकी है। भाजपा की केंद्र सरकार ने दस साल लोगों की सेवा करने के बजाय जनता की चुनी हुई सरकारों को पैसे के दम पर गिराने का काम किया, प्रधानमंत्री कोविड में लोगों से थाली बजवाते रहे, जबकि उनका काम अस्पतालों में व्यवस्था सुचारू करवाना, ऑक्सीजन मुहैया करवाने व वेंटिलेटर को चालू करवाने का भी था।

उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं, वह बायोलॉजिकल नहीं हैं। सब कुछ अपने आप हो जाता है, मैं कहता हूं कि जब अडानी के मामलों की जांच होगी तब वह कहेंगे यह परमात्मा का आदेश था। मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि यह दौरा उन्हें कब पड़ता है सुबह या शाम के समय, क्योंकि परमाणु बम का बटन आपके हाथ मे होता है। राहुल ने कहा कि आजकल चार चमचे बैठकर मोदी जी का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप आम कैसे खाते हो। अमीर, अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबको गरीब बना दूं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगने के लिए हिमाचल आ गए, लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी के समय याद नहीं आई। हिमाचल को कोई विशेष राहत पैकेज नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री व भाजपा नेता झूठ बोल रहे हैं कि आपदा राहत में करोड़ों रुपये दिए गए। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के हिस्से का पैसा हर राज्य को प्रति वर्ष किस्तों में मिलता ही है चाहे आपदा या नहीं। प्रदेश सरकार ने ओपीएस, 1500 रुपये पेंशन, सुख आश्रय योजना, विधवा महिलाओं के बच्चों को 27 साल तक मुफ्त पढ़ाने की योजना बनाकर कोई गुनाह नहीं किया है। भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति का अंत हिमाचल प्रदेश की जनता 4 जून को कर देगी।

ओपीएस के लिए चुनाव लड़ने की चुनौती कर्मचारियों को किसने दी थी:हर्षवर्धन

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सरकारी कर्मचारियों के हिमायती बनने के कोशिश न करें क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को अच्छी तरह से याद है कि किसने उन्हें पुरानी पैन्शन के लिए चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। किसने पुरानी पैन्शन पर आन्दोलन करने के लिए उन पर पानी की बौछारें छोड़ी और किसने पुलिस के डंडों से

सरकारी कर्मचारियों को पिटवाया। मुख्यमंत्री पद के अहंकार में जयराम ठाकुर ने विधानसभा में कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को अगर पैन्शन चाहिए, तो चुनाव लड़ो। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पैन्शन दी और भाजपा की सरकार बनते ही पुरानी पैन्शन बंद कर दी गई। यह भाजपा का कर्मचारी विरोधी चेहरा है।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ही कर्मचारियों की सच्ची हितैषी है और सत्ता में आने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में कांग्रेस सरकार ने 1.36 लाख कर्मचारियों को पुरानी पैन्शन प्रदान की। इसके अतिरिक्त सवा साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने सात प्रतिशत महंगाई भत्ता भी दिया है। पुलिस कर्मचारियों की डाइट मनी पांच गुणा बढ़ाकर 1000 रुपए कांग्रेस सरकार ने ही की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ-साथ पैन्शनर्स का ध्यान भी कांग्रेस सरकार ने ही रखा है। कांग्रेस सरकार ने पैन्शनर्स को दो लाख से साढ़े तीन लाख रुपए तक के वित्तीय लाभ दिए हैं। कांग्रेस सरकार ने 75 साल से ज्यादा उम्र के पैन्शनर्स को 35 प्रतिशत, 70-75 साल के बीच के पैन्शनर्स को 20 प्रतिशत, 65-70 साल के पैन्शनर्स को 18 प्रतिशत और 65 साल तक के पैन्शनर्स को 15 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया गया है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि जिन पैन्शनर्स और पारिवारिक पैन्शनर्स की मृत्यु हो चुकी है, उनके आश्रितों को पूरे एरियर का भुगतान करने के आदेश 13 मार्च 2024 को दे दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, कांग्रेस सरकार सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय लाभ उन्हें प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के पांच साल में 20 हजार सरकारी नौकरियां दी, जबकि कांग्रेस सरकार ने एक वर्ष में ही 22 हजार नौकरियां दे दी हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि भाजपा नेता केवल झूठ बोलने में माहिर हैं। आज केंद्र सरकार के फंसे एनपीएस के 9000 करोड़ रुपए करवाने के लिए हिमाचल भाजपा के नेता दवाब बना रहें हैं। भाजपा का काम केवल मात्र अड़ंगे लगाना रह गया है। महिलाओं की 1500 रुपए पेंशन रुकवाने के लिए भी भाजपा नेता चुनाव आयोग पर दवाब डाल रहे हैं। इसलिए भाजपा नेताओं को प्रदेश की जनता से माफ़ी माँगनी चाहिए।

कांग्रेस के झूठे वादों ने किया हिमाचल की जनता के साथ छल:डॉ. राजीव बिंदल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस पार्टी पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने झूठे वादों का एक बड़ा पुलंदा पेश किया था।

डॉ. बिंदल ने कहा, कांग्रेस ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट

बैठक में 22 लाख बहनों को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे। 25 लाख बिजली के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और 25 लाख किसानों का दूध और गोबर खरीदा जाएगा। इस तरह की अनेक घोषणाओं के माध्यम से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की दीवारों को भर दिया था।

डॉ. बिंदल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि डेढ़ साल के बाद भी उनकी सरकार बैक गियर में ही चल रही है। वे कहते हैं कि हमारा खजाना खाली है, फिर कहते हैं कि हमें केंद्र से कोई मदद नहीं मिलती, और फिर बीजेपी पर विरोध करने का आरोप लगाते हैं। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो फिर से झूठे वादों के साथ मैदान में उतर आये हैं। दिल्ली वाले फिर से आकर पहली कैबिनेट की बात कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि 1 लाख रुपये खटाखट, ठकाठक करेंगे।

उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस ने हिमाचल की जनता को मूर्ख बनाने का ठेका ले रखा है? हिमाचल की जनता समझदार है और जानती है कि प्रदेश की सरकार ने एक फूटी कौड़ी का भी काम नहीं किया। प्रदेश की जनता जानती है कि हिमाचल का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुरक्षित है। कांग्रेस पार्टी न तो हिमाचल की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है और न ही तुष्टिकरण के नाम पर वोट मांगने की राजनीति से बाज आ रही है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि हिमाचल की जनता अब सवाल पूछ रही है, 2022 में आपने जो बड़ी-बड़ी बातें की थीं, अब उन्हें दोबारा से क्यों दोहराया जा रहा है? उन्होंने कहा कि आज हिमाचल की जनता ने मन बना लिया है कि न तो यह सरकार हिमाचल में रहेगी और न ही इनके झूठे वादे। हिमाचल की जनता नरेंद्र मोदी की सरकार को दिल्ली में फिर से देखना चाहती है।

प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान आवश्यक:मुख्य सचिव

शिमला/शैल। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रबन्धन के संबंध में राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल की चौथी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि वर्तमान में प्लास्टिक हानिकारक प्रदूषक कारकों में से प्रमुख है। प्लास्टिक धरती, वायु और पानी को प्रदूषित करता है। गैर-जैवनिम्नीकरणीय गैर-बायोडिग्रेडेबल होने के कारण इससे उत्पन्न होने वाली प्रदूषण की समस्या विकट है। प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विशेषकर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर गंभीरता से कार्य किए जा रहे हैं ताकि प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए अधिक पर्यावरण अनुकूल और वैज्ञानिक विकल्प तैयार किए जा सकें। उन्होंने कहा कि पॉलिथीन से होने वाले खतरों के दृष्टिगत राज्य में गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बने पॉलिथीन या प्लास्टिक कैरी-बैग के उपयोग, बिक्री और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। राज्य में सभी प्रकार की वस्तुओं के व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं और विक्रेताओं पर गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बने कैरी बैग का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए अनेक महत्वाकांक्षी पहल की हैं। प्लास्टिक कचरे के समुचित प्रबन्धन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनेक अभियान क्रियान्वित किए जा रहे हैं। पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शहरी स्थानीय निकाय जैसे सभी हितधारकों के साथ राज्य ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति की है।

उन्होंने सभी उपायुक्तों को प्रत्येक शनिवार को सिंगल यूज प्लास्टिक के समुचित प्रबन्धन की प्रगति का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 'बाय बैक नीति' के अनुसार नॉन रिसाइकेबल और सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट को प्रदेश में पंजीकृत कूड़ा बीनने वालों और व्यक्तिगत परिवारों के माध्यम से 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है। नीति के तहत ब्रेड, केक, बिस्किट, कुकीज, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स या वेफर्स, कैंडीज, पनीर पफ्स, आइसक्रीम, आइसक्रीम कैंडीज, नूडल्स, चीनी कोटिड मिष्ठान वस्तुएं, साफ और सूखी पैकेजिंग, दूध, तेल, शैम्पू, हाथ धोने, तरल साबुन, दही, छाछ, जूस आदि जैसे तरल पदार्थों के पाउच या पैकेट, अनाज या कॉर्नफ्लेक्स या नाश्ता अनाज जैसी सभी प्रकार की पैकेजिंग के प्लास्टिक कचरे को हटा दिया जाएगा।

निदेशक पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डी.सी.राणा ने जिला स्तर की पहल को शामिल करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 'बाय बैक नीति' के तहत एकत्र लगभग 1300 टन प्लास्टिक को लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए और राज्य में सीमेंट कारखानों में उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को ऐसे प्लास्टिक का उपयोग करके 200 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में पूरे राज्य में जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

प्रधान सचिव शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

मुझे आशीर्वाद चाहिए-ताकतवर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित हिमाचल के लिए

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाहन के चौगान में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा भारत को जो स्पीड और स्केल चाहिए, वो सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। उन्होंने कहा की जब में हिमाचल का

प्रभारी था तब भी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानता था और आज भी मानता हूं। मोदी ने कहा की समय बदल है पर मोदी नहीं बदला है।

उन्होंने कहा की मेरे लिए न नाहन नया है और न ही सिरमौर नया है। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि आज का माहौल नया है। जब देश मोदी को जानता नहीं था, तब भी आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद और प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी। समय बदला है, लेकिन मोदी नहीं बदला है। मोदी का हिमाचल से वही पुराना रिश्ता है।

उन्होंने कहा की मुझे आशीर्वाद चाहिए। एक ताकतवर भारत बनाने के लिए, दूसरा विकसित भारत बनाने के लिए और तीसरा विकसित हिमाचल के लिए। मोदी ने कहा की हिमाचल प्रदेश सीमा से सटा हुआ राज्य है, हिमाचल के लोग एक मजबूत और ताकतवर सरकार का मतलब जानते हैं। मोदी आपके लिए जान की बाजी लगा देगा, लेकिन आप पर कभी संकट नहीं आने देगा।

पीएम मोदी ने कहा एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला, इन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में ये होगा, वो होगा। लेकिन पहली कैबिनेट में कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कैबिनेट ही टूट-फूट गई।

कांग्रेस और इंडी गठबंधन स्वार्थी है और अवसरवादी है। ये घोर सांप्रदायिक हैं, ये घोर जातिवादी हैं और ये घोर परिवारवादी हैं।

60 वर्ष तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं, उनको भी आरक्षण की जरूरत है, कांग्रेस ने इन समाज के बारे में कभी सोचा ही नहीं।मोदी ने आकर सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ।

मोदी ने कहा की कांग्रेस ने हमारे गिरिपार के हाटी समुदाय को भी आरक्षण नहीं दिया था। ये सारे काम मोदी ने आपका कर्ज उतारने के लिए किए हैं। इसके कारण आज हमारे समाज के लोगों को अलग-अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है।

आज मैं आपसे तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। मुझे आशीर्वाद मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे परिवार, मेरी जात-बिरादरी के लिए नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद चाहिए - ताकतवर भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित हिमाचल के लिए।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा यह हमारा सौभाग्य है की हिमाचल की पावन धरती पर पीएम मोदी का आगमन हुआ। आज के दौरे के बाद भाजपा और चुनावी प्रचार में बल मिलेगा, अभी की हिमाचल में चार की चार देश में 400 पार।

कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप उपस्थित रहे और मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया।

इंडी गठबंधन वालों के पास प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही नहीं है:अमित शाह

शिमला/शैल। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा 5 चरण का मतदान पूरा हो चुका है, आज छठे चरण का मतदान चल रहा है। 5

चरण में ही मोदी जी 310 पार कर गए हैं, अब छठे और सातवें में 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। 400 पार की जिम्मेदारी सातवें चरण वालों पर है।

उन्होंने कहा की हमारा तो 400 पार हो रहा है, लेकिन राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं। हमारे विधानसभा उप-चुनाव के उम्मीदवारों को भी जीता दीजिए यहां भी भाजपा की सरकार बनेगी।

अगर आप दीया लेकर भी ढूंढोगे, तो भी अनुराग ठाकुर जैसा सांसद नहीं मिलेगा। इन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की चिंता की, बल्कि भाजपा और भाजपा की विचारधारा के साथ देश भर के युवाओं को लामबंद करने का काम किया है।

शाह ने कहा की कांग्रेस के नेता हमे डराते हैं की पीओके की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मैं आज देवभूमि से कहता हूं-राहुल बाबा हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते, मैं डंके की चोट पर कहता हूं-पीओके भारत का है, रहेगा और हम उसे लेकर रहेंगे। राहुल बाबा और उनकी बहन शिमला में छुट्टियां मनाने तो आते हैं, लेकिन ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गये। ये इसलिए नहीं गये, क्योंकि ये अपने वोटबैंक से डरते हैं।

उन्होंने कहा की इंडी गठबंधन वालों के पास प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही नहीं है। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि बारी-बारी से 1-1 साल एक-एक व्यक्ति बनेगा। राहुल बाबा ये परचून की दुकान नहीं है, 140 करोड़ लोगों का देश है। इस चुनाव में एक ओर हर 6 महीने में छुट्टी मनाने वाले राहुल बाबा हैं और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर सेना के जवानों के साथ सरहद पर मिठाई खाने वाले नरेन्द्र मोदी जी हैं।

केंद्र मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश को दी गई सभी केंद्र परियोजनाएं गिनाई जो 10000 करोड़ से अधिक है। उन्होंने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार झूठी और निक्कामी है। पहली कैबिनेट में एक लाख नौकरी देने का वादा, महिलाओं को 1500 रु, गोबर खरीद जैसी कोई भी गारंटी कांग्रेस पार्टी ने पूरी नहीं की है।

हिमाचल राम मंदिर के निर्माण की संकल्प भूमि:मोदी

शिमला/शैल। मोदी ने कहा की पालमपुर यहां से ज्यादा दूर नहीं है। मैं आज याद दिलाना चाहता हूं कि पालमपुर में भाजपा की कार्यसमिति की बैठक थी, उसमें जो निर्णय हुआ था, उससे एक इतिहास रचा गया था। इसी अधिवेशन में भाजपा ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। यानी हिमाचल राम मंदिर के निर्माण की संकल्प भूमि है। हिमाचल में लिया गया वो ऐतिहासिक संकल्प सिद्ध हो चुका है। 500 साल का इंतजार, 500 साल अविरत संघर्ष चला, लाखों

लोगों ने शहादत दी। अब वो 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। ये इंतजार खत्म किया है आपके एक वोट ने, आपके वोट की ताकत ने 500 साल का इंतजार खत्म किया। आज अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, हिमाचल खुश हुआ है, देवी-देवता आशीर्वाद बरसा रहे हैं। लेकिन, कांग्रेस खुश नहीं है। अगर आपके एक वोट ने मोदी की ताकत नहीं बढ़ाई होती, तो कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं बनने देती।

मोदी ने कहा की 2024 के इस चुनाव में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन पांच चरणों में भाजपा एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की चार सीटें जुड़ जाएंगी, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि हिमाचल फिर एक बार 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। देश लगातार तीसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है।

उन्होंने कहा आपने दशकों तक कांग्रेस का शासन देखा है, कांग्रेस को ऐसा भारत पसंद है जहां गरीबी हो, संकट हो, नागरिक समस्याओं से घिरे हों। इसलिए वो देश में पुराने हालात वापस लाना चाहती है। वो देश के विकास में रिवर्स गीयर लगाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 वापस लाएंगे, सीएए को खत्म करेंगे। कांग्रेस के साथी तो कह रहे हैं कि हम देश के परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। मोदी ने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया है, भारत का नागरिक भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हों, उनके लिए एक समान नागरिक कानून होने चाहिए। लेकिन कांग्रेस समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहाने शरिया को समर्थन देती है।

इस देश को वो नहीं बना सकते, जो सिर्फ बाप-दादा की विरासत पर ही जीते हैं। इस देश को वो बनाएंगे जो मिट्टी से उठकर पहाड़ जितनी ऊंचाइयां छूते हैं। इसलिए, आज भारत का भविष्य हमारे स्टार्ट अप्स शुरु करने वाले नौजवान हैं, स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेजने वाले नौजवान हैं, खेतों में ड्रोन उड़ा रही बेटियां हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही बेटिया हैं।

लेकिन कांग्रेस उसी दकियानूसी सोच में डूबी हुई है। आपने देखा है कि अपने दम पर सफलता हासिल करने वाली बेटियों को कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही हैं, वो मंडी का अपमान है, छोटी काशी का अपमान है, हिमाचल का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है।

ये कांग्रेस, 21वीं सदी में आ ही नहीं पाई, लोग आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस उल्टा चलती है। ये 20वीं सदी की तरफ जा रही है, कांग्रेस का शाही परिवार घोर बेटी-विरोधी है, कांग्रेस महिला विरोधी है। हिमाचल में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थान हैं, कांग्रेस की सरकार तो इतनी डरपोक थी कि दलाई लामा जी का नाम लेने से भी डरती थी। मेरी तो दलाई लामा जी से अक्सर बात होती है, वो हमारी समृद्ध विरासत के प्रणेता हैं। भारत, बुद्ध का देश है और मोदी सरकार ने ज़ोर शोर से अपनी इस विरासत का प्रचार प्रसार किया है।

कांग्रेस हिमाचल को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रही है, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। मैं हिमाचल की जनता से आग्रह करूंगा कि यहां विधानसभा उप-चुनाव में भी सभी 6 सीटें भाजपा को जिताएं, हिमाचल के भविष्य सुनिश्चित करें।

इस दौरान भाजपा मंडी प्रत्याशी कंगना रनौत उपस्थित रही और पीएम मोदी जी के साथ जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया।

अग्निवीर 100 % रोजगार की गारंटी

शिमला/शैल। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब राहुल बाबा नेता बने इस देश की राजनीति में बहुत आमूलचूक परिवर्तन हो रहें है। पहले सच्चे मुद्दों को तोड़-मरोड़ कर लोगों के सामने रखा इतना तो पुल लीगल पार्टियां करती थी। मगर कभी भी झूठी बात को मुद्दा नहीं बनाया। राहुल

गांधी ने एक नई परंपरा शुरू की है, फिर झूठी बात को ही मुद्दा बनाया गया और इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण अग्निवीर योजना है।

अग्निवीर योजना के प्रति देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल के बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों का कोई भविष्य ही नहीं है, इनका जीवन बर्बाद हो जायेगा। दरअसल इस योजना के अंतर्गत अगर 100 जवान अग्निवीर बनते हैं तो उसमें से 25 प्रतिशत तो सीधा सेना में परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगें और 75 प्रतिशत बचे हुये जवानों के लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपनी पुलिस फोर्स में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत रिजर्वेशन किया है और केंद्र सरकार के पैरामिलिटरी फोर्स में भी 10 प्रतिशत रिजर्वेशन किया है। इनको रिज़र्व सीटों के उपरान्त सेलेक्शन में भी बहुत सी रियायतें दी हैं जैसे उम्र की रियायत, इग्ज़ैमिनेशन में कुछ ऐडवांटेजस और फिजिकल टेस्ट भी नहीं करने पडेंगे। इन सभी रियायतों के बाद शायद ही कोई अग्निवीर ऐसा बचेगा जो स्टेट की पुलिस फोर्स या सेंटर पैरा मिलिट्री फोर्स में ना आया हो। इसके अलावा भी बहुत से प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीस और कंपनियों ने भी अग्निवीर के लिए प्राथमिकता तय की है। अब एक युवा 4 साल सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग करेगा और सक्षम हो जायेगा 4 साल उसको अच्छी तनख्वाह के साथ-साथ 4 साल के बाद पैन्शन नुमा पूरे जीवन की नौकरी भी मिलेगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

शिमला और मंडी में कांग्रेस की रणनीतिक कमजोरी नुकसान देह हो सकती है

क्या विधानसभा उपचुनाव के लिये सरकार और कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार नहीं है

शिमला/शैल। चुनाव प्रचार अन्तिम चरण में पहुंच चुका है। कांग्रेस और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में चुनावी रैलियां संबोधित कर गया है। इससे दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय एजेंडे सामने आ चुके हैं। लेकिन क्या प्रदेश में राष्ट्रीय एजेंडे कहीं चुनाव का मुद्दा बन भी पाये हैं यह अपने में बड़ा सवाल हो गया है। क्योंकि प्रदेश में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के लिये हो रहे छः उपचुनाव ने चुनावी एजेंडे को ही बदल दिया है। विधानसभा के लिये हो रहे छः उपचुनावों पर प्रदेश सरकार का भविष्य टिका हुआ है। यह छः उपचुनाव राज्यसभा में चुनाव में कांग्रेस के छः और तीन निर्दलीयों द्वारा भाजपा के पक्ष में वोटिंग करने से उत्पन्न स्थिति के कारण हो रहे हैं। इन नौ लोगों के भाजपा के पक्ष में वोट करने से राज्यसभा में कांग्रेस और भाजपा के 34-34 वोट हो गये थे और पर्ची के माध्यम से चुनाव परिणाम का फैसला होने से यह निर्णय भाजपा के पक्ष में आ गया। इस परिणाम के बाद कांग्रेस ने अपने छः लोगों को दल बदल कानून के तहत सदन की सदस्यता से बाहर कर दिया। लेकिन तीन निर्दलीयों को कानूनी दाव पेचों में उलझाकर आज तक उनके त्यागपत्र स्वीकार नहीं किये हैं। जबकि छः कांग्रेसियों ने अपने निष्कासन और तीनों निर्दलीयों ने त्यागपत्र देने के बाद भाजपा ज्वाइन कर ली थी। भाजपा ने सभी नौ लोगों को उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार भी बना दिया था। यदि निर्दलीयों की तर्ज पर ही कांग्रेस के छः लोगों के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेकर उनके भाजपा में जाने को लटका दिया जाता तो शायद यह छः उपचुनाव न हो रहे होते। लेकिन ऐसा इसीलिये नहीं किया गया क्योंकि उनके जाने से सरकार को कोई खतरा नहीं था। आज इन छः का भाजपा में जाना चुनाव का कांग्रेस की ओर से मुख्य मुद्दा बना हुआ है। यदि कांग्रेस के पास यह मुद्दा न आता तो किन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाता। निश्चित रूप से तब सरकार की 15 माह की परफारमैन्स और विधानसभा चुनाव में दी गयी गारंटीयां इस समय बड़े सवाल होते। सरकार द्वारा पन्द्रह माह में दिया गया कर्ज चर्चा का विषय होता। भ्रष्टाचार न तो जयराम सरकार के समय में कोई मुद्दा रहा और न ही अब सुक्खू सरकार के समय में कोई मुद्दा है। जयराम ने भाजपा के आरोप पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की। ठीक उसी तर्ज पर आज सुक्खू सरकार भी कांग्रेस के आरोप पत्र पर कोई कारवाई नहीं कर रही है। बल्कि मुख्यमंत्री जिस तरह धन बल के सहारे सरकार गिराने के प्रयास करने का आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं उसका कोई ठोस जवाब दिया जा रहा है। अभी धर्मशाला में मुख्यमंत्री ने सुधीर शर्मा पर भू माफिया होने के जो आरोप लगाये हैं और सुधीर शर्मा ने दस्तावेजी प्रमाणों के साथ मुख्यमंत्री को घेरा है उस पर भी भाजपा नेतृत्व की चुप्पी अपने में बहुत कुछ बयां कर जाती है। इस चुप्पी से यह संकेत उभर रहे हैं कि दोनों पार्टियों में लोकसभा और विधानसभा को लेकर कोई अघोषित सहमति है। चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की कार्यशैली से यह संदेह पुख्ता हो जाता है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सारे वायदों के बावजूद के 0.6% के अंतर से सरकार की जीत हुई है और पन्द्रह माह में इस अन्तर को सरकार बड़ा नहीं कर पायी है।

शिमला लोकसभा

शिमला लोकसभा में कांग्रेस का विधायकों में बहुमत है। इसी क्षेत्र से पांच मंत्री और तीन मुख्य संसदीय सचिव हैं। इसी के साथ सलाहकार और ओएसडी भी इस क्षेत्र से दूसरों की तुलना में ज्यादा हैं। लेकिन यह सब होने के बाद बद्दी क्षेत्र के उद्योगों को लेकर जो सवाल उठे और उद्योग मंत्री को एक समय मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ा। सिरमौर के हाटी प्रकरण पर सरकार की कार्यप्रणाली सवालों में आयी। सोलन में भाजपा का एक भी विधायक न होते हुये भी नगर निगम सोलन में सरकार की फजियत होना सरकार और संगठन की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल है। इसी कार्यशैली के कारण दोनों सहकारी बैंकों के निदेशकों के चुनाव में पार्टी की फजीहत हुई है। सरकार होने के बाद भी ऐसा हुआ दूसरी ओर संगठन के स्तर पर चौपाल में कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉ. सुभाष मंगलेट का भाजपा में शामिल होना अपने में एक सवाल है। इसी तरह अर्की में पिछले विधानसभा चुनाव में आजाद लड़े राजेन्द्र ठाकुर का भाजपा में जाना कांग्रेस के लिये नुकसान देह माना जा रहा है। राजेन्द्र ठाकुर को हॉलीलाज का विश्वस्त माना जाता है। पूर्व मंत्री गंगूराम मुसाफिर का कांग्रेस में वापस आना जिस ढंग से लटकाया गया था उससे भी कांग्रेस और संगठन में सब ठीक न होने का ही संदेश गया है। चुनाव के समय यह सब होना पार्टी की चुनावी सेहत के लिये स्वस्थ नहीं माना जाता है। फिर यह सीट पिछले दो चुनावों से भाजपा के पास है।

मंडी लोकसभा क्षेत्र

मंडी लोकसभा सीट में विधायकों का बहुमत भाजपा के पास है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी मंडी से ही हैं। यहां से भाजपा ने पद्म श्री कंगना रणौत को प्रत्याशी बनाया है। सफल अभिनेत्री और फिल्म निदेशक कंगना रणौत पहली बार राजनीति में आ रही हैं। पारिवारिक पृष्ठ भूमि कांग्रेस की रही है। राजनीति में उनका योगदान नहीं रहा है। लेकिन इस चुनाव प्रचार के दौरान ही अपनी बेवाकी से जिस कदर चर्चित हो गयी हैं वह अपने में ही एक उपलब्धि बन गयी है। क्योंकि चुनावी बहसों में जब उम्मीदवार का खानपान और पहरावा चर्चा का विषय बन जाये तो यह माना जाता है कि बड़ी सफलता के साथ उम्मीदवार ने अपने को चर्चाओं के केंद्र में स्थापित कर लिया है। ऐसे में हर व्यक्ति उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करता है। इसी प्रयास के परिणाम स्वरुप कंगना पर यह आरोप लगे कि वह तो राजनीतिक पर्यटक हैं जीत कर मुंबई लौट जायेंगी। यह आक्षेप ही एक तरह से कंगना की उपलब्धि बन गये। क्योंकि जब कंगना से आपदा के दौरान उसके सहयोग को लेकर सवाल उठाये गये तब यही सवाल उसकी उपलब्धि बन गये। क्योंकि यही सवाल तो मुख्यमंत्री प्रदेश के सांसदों से भी कर चुके हैं। कंगना पर उठते सवाल जब उसके निजी जीवन पर आ गये तो पलट कर वही सवाल कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य पर चिपक गये। विक्रमादित्य के पास स्व.वीरभद्र की जो विरासत थी उसको उन्हें केन्द्र में लाना पड़ा। सरकार की पन्द्रह माह की परफारमैन्स पर किसी समय खुद ही उठाये सवालों का जवाब स्वयं ही देने की बाध्यता आ खड़ी हुई। चुनावी पोस्टरों पर स्व.वीरभद्र का फोटो लाकर स्वयं ही अपने को राजनीतिक विरासत के सहारे का मोहताज बना दिया। जबकि विक्रमादित्य सिंह को वीरभद्र होने में तो समय लगेगा। ऐसे में अगर यह कहा जाये की विक्रमादित्य अनचाहे ही कंगना और जय राम के राजनीतिक ट्रैप का शिकार हो गये हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि कंगना और जयराम पर विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह की टिप्पणियों के वीडियो का जिस तरह से इन लोगों ने जवाब दिया है उससे इस ट्रैप की राजनीति स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि विशलेष्कों के अनुसार राजनीतिक धरातल पर विक्रमादित्य और कंगना में कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन सलाहकारों ने दोनों को एक ही राजनीतिक धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया वह आगे चलकर सारी राजनीति पर प्रश्न चिन्ह बन गया है।

बड़सर में 55 लाख कैश मिलने का आरोप कोरा झूठः जयराम

✔ हमीरपुर और कांगड़ा लोकसभा में कांग्रेस का रक्षात्मक होना घातक होगा
✔ सुधीर शर्मा के आरोपों ने बदला परिदृश्य

शिमला/शैल। इन चुनावों के चुनाव प्रचार का आकलन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इसमें छः विधानसभा उपचुनावों को लोकसभा चुनाव से ज्यादा अधिमान दिया है। क्योंकि विधानसभा उपचुनाव का आने वाले समय में सरकार की सेहत पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस संभावित प्रभाव के साये में चल रही कांग्रेस ने जहां शिमला मण्डी में रणनीतिक भूलें की वहीं पर हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ रस्मी आक्रामकता से आगे नहीं बड़े। जबकि हमीरपुर में अनुराग के खिलाफ दिल्ली में वृन्दा करात द्वारा उठाया गया मामला अपने में अभी भी गंभीर बना हुआ है। लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में इस मुद्दे का एक बार भी कहीं जिक्र तक नहीं आया। इसी तरह कांगड़ा में केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा ऊना की एक ब्रांच के माध्यम से लाहौल-स्पीति में दिया गया ऋण एक बड़ा मुद्दा रहा है। इस मुद्दे की आंच तो एक समय शान्ता कुमार तक पहुंच गई थी। यह मुद्दे मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक हर प्रमुख कांग्रेस नेता के संज्ञान में रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार में इस पर किसी ने सवाल तक नहीं उठाया। बल्कि कांगड़ा में आनन्द शर्मा की स्वीकार्यता बनाने के लिए मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि यदि नरेन्द्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं तो आनन्द कांगड़ा से क्यों नहीं। कांगड़ा और हमीरपुर में कांग्रेस का चुनाव प्रचार आक्रामक होने की बजाये रक्षात्मक रहा है और यही नुकसानदेह होने की प्रबल संभावना है। दूसरी ओर इन दोनों क्षेत्रों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिये पूरी आक्रामकता के साथ मुख्यमंत्री ने यह परोसा की यह लोग पन्द्रह-पन्द्रह करोड़ में बिक गये हैं। इस पर मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि के मामले दायर हो गये हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुये मुख्यमंत्री ने सुधीर शर्मा को भू-माफिया की संज्ञा देते हुये यह आरोप लगा दिया कि उसने अपने ड्राइवर के नाम पर 10 करोड़ की 82 संपत्तियां खरीदी है। लेकिन इस आरोप के कोई प्रमाण जारी नहीं किये। इसके जवाब में सुधीर शर्मा ने पूरे दस्तावेजी प्रमाणों के साथ मुख्यमंत्री के खिलाफ हमला बोला है। सुधीर शर्मा के आरोपों के परिणाम दूरगामी और गंभीर होंगे। यही नहीं बडसर में 55 लाख रुपये मिलने के एक मामले को मुख्यमंत्री ने अपने ब्यानों में यहां तक उछाला है कि इस कथित कैश को लखनपाल के नाम तक लगा दिया। मुख्यमंत्री द्वारा यह आरोप लगाये जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बडसर गये। जयराम ठाकुर ने जनसभा में यह कहा कि उन्होंने यह कथित 55 लाख पकड़े जाने की घटना का मीडिया और प्रशासन के माध्यम से यह जानकारी जुटाने का प्रयास किया कि किस से यह 55 लाख किस अधिकारी ने पकड़े हैं। किस थाने में इसको लेकर मामला दर्ज हुआ है। जयराम ठाकुर ने भरी सभा में यह कहा है कि उनको मिली जानकारी के अनुसार ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है। जयराम ने मुख्यमंत्री के इस आरोप को कोरा झूठ करार दिया है। जयराम का यह खुलासा पूरे प्रदेश में फैल गया है। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के नाम पर नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कोरा झूठ बोलने का आरोप लगना सारे परिदृश्य को ही बदल देता है। सुधीर के आरोपों के साथ जयराम ठाकुर का यह खुलासा पूरे चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है।